0.1 फीसद ब्याज दरें घटा दी हैं सरकार ने पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना सहित लगभग सभी लघु बचत योजनाओं पर। नई दरें एक जुलाई से शुरू हो रही तिमाही के लिए प्रभावी होंगी।

आपदा प्रबंधन में दुनिया में अव्वल बने भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नई दिल्ली में शनिवार को आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों के वार्षिक सम्मेलन के दौरान प्रदर्शनी में अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन उपकरणों का अवलोकन करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जागरण

गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन उपकरणों के विकास और उत्पादन में 'मेक इन इंडिया' पर जोर दिया। शाह ने कहा कि डीआरडीओ के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन की स्वदेशी तकनीक विकसित की जानी चाहिए। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत दुनिया में अव्वल होना चाहिए। जब दुनिया के कई सारे देश आपदा प्रबंधन पर भारत के मॉडल को अपनाने और समझने पर मजबूर होंगे, तब हमें समझना चाहिए कि हमने कुछ सफलता अर्जित की है।

शाह ने शनिवार को आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि समुद्री चक्रवात की तरह बाढ़ और जंगल में फैलने वाली आग से होने वाले नुकसान को रोकने में महारत हासिल करना जरूरी है। इस दिशा में अभी तक उतना काम नहीं हुआ है। चक्रवात फणि के समय में जान-माल की रक्षा करने के लिए एनडीआरएफ की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत ने काफी कम समय में ही आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बड़ी विशेषज्ञता हासिल की है लेकिन अभी और कई काम किये जाने हैं।

अमित शाह के अनुसार आपदा प्रबंधन एजेंसियों के लिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण जंगलों में आग लगने वाली घटनाओं पर काबू पाने की चुनौती बची हुई है। पहाड़ों में जंगलों में लगने वाली आग से लोगों को बचाने के साथ ही, पर्यावरण की सुरक्षा और पेड़ों को बचाना भी हमारा दायित्व है। इसके साथ ही उन्होंने हर साल बाढ़ के कारण होने वाले जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन एजेंसियों को काम करने का आह्वान किया। उनका कहना था कि देश के विभिन्न भागों में आने वाली बाढ़, उसके कारणों और उससे होने वाले नुकसान के विस्तृत डाटा के विश्लेषण से उससे बचने के उपाय खोजे जा सकते हैं।

इसके साथ ही अमित शाह ने आपदा के समय जिला स्तर पर पूर्व निर्धारित तंत्र विकसित करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि देश भर में आपदा प्रबंधन के जितने संसाधन बिखरे हुए हैं, इसका भी एक रजिस्टर एनडीआरएफ के पास होना चाहिए। हर जिला मुख्यालय में आपदा प्रबंधन की एक टीम होना चाहिए और उनके पास ऐसी लिस्ट होनी चाहिए जिसमें उस क्षेत्र के बड़े उद्योगों की जानकारी हो। साथ ही आपदा से निबटने के लिए उनके पास मौजूद उपकरणों की भी जानकारियां हों। इसके साथ ही यह साफ होना चाहिए आपदा की स्थिति में जिला स्तर पर नेतृत्व किसके हाथ में होगा, ताकि अंतिम समय भ्रम की कोई स्थिति पैदा ना हो।

करतारपुर कॉरिडोर पर भारत ने रखा प्रस्ताव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भारत ने करतारपुर कॉरिडोर पर वार्ता को आगे जारी रखने के लिए नई तारीख का प्रस्ताव पाकिस्तान सरकार के सामने रख दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान विदेश मंत्रालय को भेजे गये पत्र में 11 से 14 जुलाई के बीच पाकिस्तान सीमा में वाघा बार्डर पर वार्ता की पेशकश की गई है। दोनों देशों के बीच तकनीकी स्तर पर तीन दौर की बातचीत हो चुकी है। भारत में चुनाव आ जाने की वजह से बातचीत प्रभावित हो रही थी। पाकिस्तान इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो कॉरिडोर से तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान में स्थित करतारपुर गुरुद्वारे तक सुरक्षित व आसानी से पहुंचाने पर बातचीत की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा किस तरह की ढांचागत सुविधा दी जाएगी, इसको लेकर भी अंतिम फैसला आगामी बैठक में हो सकती है।

भारतीय कैबिनेट ने नवंबर 2018 में फैसला किया था कि तीर्थयात्रियों को सुविधाजनक तरीके से गुरुद्वारा करतारपुर साहिब तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन ढांचागत सुविधा विकसित की जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान सरकार की तरफ से भी इस बारे में एलान किया गया था कि वह भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए अपनी सीमा खोलेगा। भारत वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक टर्मिनल व चार लेन की बेहतरीन गुणवत्ता वाले राजमार्ग का निर्माण कर रहा है। इसका 45 फीसद काम पूरा हो चुका है। इस कॉरिडोर को नवंबर, 2019 में खोलने की तैयारी है ताकि तीर्थयात्री गुरु नानक देव की 550वीं वर्षगांठ के अवसर पर करतारपुर गुरुद्वारा जा सकें।

21 हजार पेड़ बचाने को ठाणे बुलेट ट्रेन स्टेशन का डिजाइन बदला

नई दिल्ली, आइएएनएस/प्रेट्र: मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर (बुलेट ट्रेन) प्रोजेक्ट में वन्यजीव, वन विभाग और तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) से सभी मंजूरियां ले ली गई हैं। इसके चलते, मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबी बुलेट ट्रेन परियोजना का काम देख रहे नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने महाराष्ट्र में कम से कम सदाबहार पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए ठाणे स्टेशन का डिजाइन दोबारा बनाया है। इस बदलाव के कारण अब 21 हजार सदाबहार वृक्षों को कटने से बचा लिया गया है।

- पहले कटने थे 53 हजार सदाबहार पेड़, अब कटेंगे 32,044 ही
- दोबारा होगा वनीकरण, पांच गुना अधिक 1,60,220 पौधे लगाए जाएंगे

प्रतीकात्मक

एनएचएसआरसीएल के प्रबंध निदेशक अचल खरे ने शनिवार को एक बयान में कहा कि पहले 53,000 सदाबहार पेड़ काटे जाने वाले थे, लेकिन नई डिजाइन के बाद लगभग 32,044 पेड़ ही प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वन्यजीव, वन और तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) से सभी जरूरी मंजूरियां ले ली गई हैं। वन विभाग ने हालांकि कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है। पर्यावरण मंत्रालय ने शर्त रखी है कि ठाणे स्टेशन के डिजाइन की समीक्षा की जाएगी जिससे प्रभावित क्षेत्र सीमित किया जा सके। उन्होंने कहा कि हम ठाणे स्टेशन की मौजूदा स्थिति बदले बिना ही सदाबहार वन क्षेत्र के प्रभावित भाग को कम करना चाहते थे। हमने जापान के इंजीनियरों से इसी पर चर्चा की और उसी अनुसार बदलाव किए। एनएचएसआरसीएल के प्रबंध निदेशक ने कहा कि यात्री परिसर पार्किंग क्षेत्र की तरह है और पैसेंजर हैंडलिंग एरिया को अब सदाबहार वन क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। स्टेशन की स्थिति वही है लेकिन दोबारा डिजाइन करने के बाद सदाबहार क्षेत्र के पूर्व के 12 हेक्टेयर की तुलना में अब सिर्फ तीन हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। उन्होंने बताया कि इस तरह 21,000 सदाबहार पेड़ों को कटने से बचाया गया है। अब इस पूरी परियोजना से 32,044 सदाबहार पेड़ ही प्रभावित होंगे। इससे पहले लगभग 53,000 सदाबहार पेड़ प्रभावित हो रहे थे।

सदाबहार वन सदाबहार पेड़ों और झाड़ियों का एक समूह है जो तटीय इंटरटाइडल जोन में पनपते हैं। यह कम पानी और कठिन जलवायु में भी सदा हरे-भरे रहते हैं। ये सभी पेड़ कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगते हैं। खरे ने यह भी बताया कि एनएचएसआरसीएल विभाग इसके बाद दोबारा वनीकरण करेगा। इसके लिए एनएचएसआरसीएल सदाबहार वन के प्रत्येक पेड़ के लिए उनके विभाग की सदाबहार सेल 1:5 के अनुपात में मुआवजा जमा करेगी।

खरे ने बताया कि 32,044 सदाबहार पेड़ों को काटने के बाद लगभग 1,60,220 सदाबहार का पौधरोपण किया जाएगा और इसका पूरा खर्चा एनएचएसआरसीएल उठाएगा। सदाबहार के नये पौधे सदाबहार सेल की देखरेख में ही उगाए जाएंगे।

पीएमओ ने लिया संज्ञान : मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर (बुलेट ट्रेन) प्रोजेक्ट के तहत ठाणे स्टेशन के निर्माण के लिए 54 हजार सदाबहार पेड़ काटे जाने को रोकने की एक पर्यावरण संगठन की अपील पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने संज्ञान लिया है। एक पर्यावरण संगठन ने इस संबंध में पीएमओ से 25 जून को गुहार लगाई थी। शुक्रवार को ही पीएमओ ने संगठन को इसका जवाब देते हुए कहा कि यह मामला पर्यावरण विभाग के वैज्ञानिक महेंदर फुलवारिया को सौंप दिया गया है। वह इस मामले पर अपनी कार्यप्रगति रिपोर्ट देंगे।

राहुल पर 'अनिर्णय' में छिपा कांग्रेस का 'निर्णय'

संशय बरकरार ▶ पार्टी के वर्तमान हालात पर सटीक बैठता है पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का सूत्र वाक्य

दोराहे पर खड़ी कांग्रेस, दुविधा और बेचैनी में हैं पार्टी के कार्यकर्ता

संजय मिश्र, नई दिल्ली

'निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय होता है।' कांग्रेस के दिग्गज नेता और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का यह चर्चित सूत्र वाक्य कांग्रेस के मौजूदा हालात को बिल्कुल सटीक बयान कर रहा है। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश के महीने भर बाद भी दोराहे पर खड़ी कांग्रेस की हालत को लेकर पार्टी कैडर की दुविधा और बेचैनी भले बढ़ रही हो, मगर अनिर्णय की यह स्थिति वास्तव में कांग्रेस की पुरानी सियासी शैली का हिस्सा रही है। पार्टी नेतृत्व जब कभी दुविधा में रहा है तब अनिर्णय की स्थिति को उसने अपना रक्षा कवच बनाया है।

ऐसे में कनिष्ठों के इस्तीफे का दांव चलकर वरिष्ठ नेताओं को अनिर्णय के लिए जिम्मेदार ठहराने का संदेश भले दिया जाए पर हकीकत यही है कि पार्टी का शिखर नेतृत्व राहुल गांधी के अडिग रुख के बावजूद उनके विकल्प पर गौर करने से हिचक रहा है। ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस नेतृत्व के एक इशारे पर नेताओं के इस्तीफे की झड़ी लग गई होती।

इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक के दौर में माखनलाल फोतेदार, आरके धवन हों या अहमद पटेल हाईकमान की ओर से इन सिपहसालारों का नेताओं को किया गया इशारा ही काफी होता था। कांग्रेस की इस कार्य संस्कृति के उदाहरणों के बावजूद राहुल के इस्तीफे के महीने भर बाद भी एके एंटनी, केसी वेणुगोपाल और गुलाम नबी आजाद जैसे निकट सलाहकारों ने वरिष्ठ नेताओं को ऐसा कोई संदेश नहीं दिया। इसलिए यह सवाल तो उठता ही है कि वरिष्ठों का इस्तीफा ही पार्टी के नए सिरे से पुनर्गठन में रोड़ा है तो फिर अभी तक चुप्पी क्यों बरती गई? खासकर तब, जब कांग्रेस कार्यसमिति ने इस्तीफे की पेशकश ठुकराते हुए राहुल को आमूल-चूल बदलाव का ब्लैंक चेक दे दिया था। कांग्रेस के सियासी भविष्य की वाजिब चिंता कर रहे कार्यकर्ताओं के लिए यह बात भी कम परेशान करने वाली नहीं है कि कभी हाईकमान के इशारे पर इस्तीफे सहित किसी भी कदम के लिए बिछ जाने को पार्टी नेता हर पल तैयार रहते थे। मगर आज राहुल गांधी के खुले इशारे के बाद भी नेता इस्तीफा देने से परहेज कर रहे हैं। इसका निहितार्थ तो यही निकलेगा कि इस्तीफे की पेशकश कर राहुल ने पार्टी में अपनी अथॉरिटी को खुद ही कमजोर किया है।

राहुल गांधी फाइल फोटो

चुनावी हार के शुरुआती पोस्टमॉर्टम में राहुल ने वरिष्ठ नेताओं की भूमिका पर भी खूब उंगली उठाई और पार्टी में बदलाव के लिए उनके अवरोधों की ओर इशारा किया। बेशक पार्टी की सियासी दुर्गति के लिए नेताओं की जिम्मेदारी को नकारा नहीं जा सकता। सच्चाई यह भी है कि शीर्ष नीति नियामक इकाई कांग्रेस कार्यसमिति से लेकर संगठन के पदों पर बैठे नेताओं का चयन तो खुद राहुल ने किया था। बतौर अध्यक्ष जब कमान संभाली तो पार्टी में उनके लिए कोई चुनौती नहीं थी। आज वह इस्तीफे का फैसला वापस ले लें तो भी पार्टी खुश ही होगी। इसलिए यह सवाल लाजिमी है कि अड़चन वाले नेताओं से तब किनारा क्यों नहीं किया गया। दिग्विजय सिंह और जर्नादन द्विवेदी जैसे वरिष्ठ नेताओं को राहुल ने अपनी टीम से बाहर किया तब सवाल नहीं उठा। जो यह साबित करता है कि निर्णायक फैसले लेने के लिए नेतृत्व के समक्ष चुनौती जैसी कोई स्थिति नहीं थी। चुनाव में हार के लिए कांग्रेस घोषणापत्र में जम्मू एवं कश्मीर से एएफएसपीए हटाने जैसे विवादित मुद्दों को शामिल करने की बात आनंद शर्मा जैसे नेता अब कबूल कर रहे हैं। दिलचस्प बात है कि शर्मा सरीखे नेता घोषणापत्र से लेकर पार्टी की अहम चुनावी रणनीति के प्रमुख रणनीतिकारों में शामिल थे। पार्टी के जमीनी नेता और कार्यकर्ता ऐसे विवादित मुद्दे हों या फिर राफेल के कथित भ्रष्टाचार का दांव, चुनाव अभियान में इसके उलटा पड़ने का संदेश भेज रहे थे। मगर तब ये रणनीतिकार ही इस हकीकत को खारिज कर रहे थे लेकिन इनकी जवाबदेही का सवाल तो अब कहीं चर्चा में भी नहीं है।

कांग्रेस की बड़ी हार और कमजोर हुई सियासी जमीन का संकट राहुल के इस्तीफे के बाद जिस तरह पार्टी के नेतृत्व के संकट में तब्दील हो चुका है उसमें असल एजेंडा पीछे छूटता दिख रहा है। पार्टी क्यों हारी और कहां-कहां चूक हुई इस पर सभी उम्मीदवारों से सीधा संवाद कर जमीनी सच्चाई जानने जैसी कोई पहल नहीं होना यह दर्शाता है। राहुल खुद इस्तीफे पर अडिग हैं तो फिर उनके उत्तराधिकारी के चयन में अनिर्णय की लंबी स्थिति पार्टी का भला तो नहीं ही करेगी। कार्यकर्ताओं के लिए यह चिंता की बात तो है कि नीचे पार्टी की जमीन सिमट रही है और ऊपर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। अनिर्णय की यह स्थिति पार्टी पर पकड़ को लेकर नेतृत्व के द्वंद्व को भी दर्शाता है। लोकसभा में जब पार्टी को आज मुखर वाक्पटु चेहरे की जरूरत है तब शशि थरूर या मनीष तिवारी की जगह अधीर रंजन चौधरी का नेता के रूप में चयन भी कुछ इसी ओर इशारा करता है। नए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए एके एंटनी हों या कई बार से अपनी लोकसभा सीट तक नहीं जीत पाने वाले मुकुल वासनिक जैसे नेता, उनका नाम उछालने का प्रयास भी कुछ ऐसा ही है। जमीनी सियासत में अप्रासंगिक हो चुके इन नेताओं की दस जनपथ से निकटता किसी से छुपी नहीं है।

'एक देश-एक राशन कार्ड' के लिए राज्यों को मिला समय

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' व्यवस्था लागू करने के लिए राज्यों को 30 जून 2020 तक का समय दिया है। इस व्यवस्था के तहत लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से से सस्ता राशन खरीद सकता है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, 'अगले साल 30 जून 2020 तक पूरे देश में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' व्यवस्था को बिना किसी देरी के लागू कर दिया जाएगा। हमने इस बारे में राज्यों को पत्र लिखा है।'

- केंद्र सरकार ने 30 जून 2020 तक का समय दिया

रामविलास पासवान फाइल फोटो

पासवान ने कहा कि नई प्रणाली से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि यदि कोई गरीब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे राशन मिलने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। नई प्रणाली से फर्जी राशन कार्ड भी समाप्त होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन के एजेंडे में शामिल कार्यक्रमों में यह भी एक कार्यक्रम है।

पासवान ने कहा कि लाभार्थियों को देश के किसी भी राशन की दुकान से खाद्यान्न खरीदने के लिए अपना आधार कार्ड दिखाना आवश्यक है। यदि लाभार्थी विशेष रूप से पंजीकृत राशन की दुकान से अपना खाद्यान्न खरीदना चाहता है तो राशन कार्ड पर्याप्त होगा। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 89 फीसद लाभार्थियों के आधार कार्ड सिस्टम से जुड़ चुके हैं, जबकि 77 फीसद राशन दुकानों में पीओएस (पाइंट ऑफ सेल) स्थापित हैं। 22 राज्यों में 100 प्रतिशत पीओएस मशीनें लगी हैं और नई प्रणाली लागू करने में कोई समस्या नहीं है।

इन राज्यों में पहले से ही व्यवस्था : पासवान के मुताबिक दस राज्य पहले से ही पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा शामिल हैं। दिल्ली ने साल भर पहले पीडीएस पात्रता की पोर्टेबिलिटी को लागू किया था, लेकिन बाद में इसे रोक दिया।

लिंचिंग पर सांप्रदायिक रंग न चढ़ने दें : नकवी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मुंबई में शनिवार को हज हाउस के नवीनीकृत हॉल के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का स्वागत करतीं महिलाएं। एएनआइ

झारखंड में युवक की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना को 'जघन्य अपराध' करार देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। मुंबई के हज हाउस में पुनर्निर्मित हॉल का उद्घाटन करने पंहुचे केंद्रीय मंत्री ने झारखंड की घटना पर साफ कहा कि जो लोग भी इस मामले में शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के मामलों में सियासत की जगह भी नहीं होनी चाहिए।

नकवी ने कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुसलिम समुदाय के लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा, 'कोई भी नकारात्मक एजेंडा, विकास और सौहार्द के माहौल को खराब न करने पाए।' पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र को सकारात्मक ताकत बनाना होगा, नकारात्मक कमजोरी नहीं। नकवी ने अपने संबोधन में भारतीय संस्कृति और भारत में वर्षों से रह रहे मिले-जुले समाज की विशेषताओं पर कहा कि भारत की पंथनिरपेक्षता की मजबूत नींव बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की सहिष्णुता के संस्कार से तैयार हुई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा पंथनिरपेक्ष-लोकतांत्रिक देश इसलिए है, क्योंकि जब बंटवारे के बाद पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन रहा था तब हिंदुस्तान के बहुसंख्यक हिंदू समाज ने पंथनिरपेक्षता का रास्ता चुना।

नकवी ने अपने भाषण में आगे कहा कि अलग-अलग भाषा, आस्था, खान-पान, रहन-सहन के बावजूद भारत की इसी संस्कृति और संस्कार ने हमें एकता की मजबूत डोर से बांध रखा है। आज भारत में अल्पसंख्यक पूरी तरह से अपने धार्मिक-सामाजिक सरोकार की स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की इसी एकता और सौहार्द की साझा संस्कृति ने आतंकवाद और इंसानियत के अन्य दुश्मनों को परास्त किया है और देश में अलकायदा और आइएस जैसी शैतानी ताकतों की जड़ों को जमने नहीं दिया। भारत का मुस्लिम समाज अच्छी तरह जानता है कि आतंकवाद इंसानियत ही नहीं इस्लाम का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। नकवी ने सरकार की नीतियों को सराहते हुए कहा कि वर्ष 2019 में दो लाख भारतीय मुसलमान बिना किसी सब्सिडी के हज यात्रा करेंगे। हमारी ईमानदार-पारदर्शी व्यवस्था का नतीजा है कि सब्सिडी खत्म होने के बाद भी हज यात्रियों पर गैर जरूरी बोझ नहीं पड़ने पाया। देश के इतिहास में सबसे ज्यादा भारतीय मुसलमान इस वर्ष हज यात्रा पर जाएंगे।

इस साल एच1एन1 वायरस से हुई 1076 लोगों की मौत

नई दिल्ली, एएनआइ : देशभर में इस साल 23 जून तक एच1एन1 वायरस की चपेट में आने से 1,076 लोगों की जान गई और 26,140 लोग संक्रमित हुए हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोकसभा में गत दिवस दी। पिछले साल 15,226 संक्रमण और 1113 लोगों की मौत का मामला सामने आया था। एच1एन1 वायरस से स्वाइन फ्लू फैलता है।

कांग्रेस के अदूर प्रकाश द्वारा शुक्रवार को पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि इस वायरस से राजस्थान में सबसे ज्यादा 205 लोगों की मौत हुई है। यहां पर 5,021 लोग इस वायरस से संक्रमित हुए। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जहां पर संक्रमित लोगों की संख्या 1692 जबकि मृतकों की संख्या 189 हैं। गुजरात में मरने वालों की संख्या 149 रही जबकि संक्रमित लोगों की संख्या 4,772 रही। मध्य प्रदेश में 653 लोगों के संक्रमित होने की बात सामने आई जबकि यहां पर मृतकों की संख्या 146 रही। कर्नाटक में 1736 लोग संक्रमित हुए और 87 लोगों की मौत हुई। सूची में हिमाचल प्रदेश सातवें नंबर पर रहा। यहां पर 333 लोग पॉजिटिव पाए गए जबकि वायरस की चपेट में आने से 41 लोगों की जान गई।

राम माधव बोले, जम्मू-कश्मीर से खत्म होगा अनुच्छेद 370

नई दिल्ली, एएनआइ : भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव ने फिर दोहराया कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 हटेगा और जम्मू-कश्मीर की समस्या के लिए कांग्रेस और नेशनल कान्फ्रेंस ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक अनुच्छेद 370 का सवाल है तो हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता सबको पता है। हम शुरुआत से ही इसके खिलाफ रहे हैं। सरकार सही समय पर अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी।

एएनआइ से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब इसे लाया गया था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने खुद कहा था कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है और यह अपने आप खत्म हो जाएगी। यहां तक कि नेहरू भी इसे हटाना चाहते थे।

कांग्रेस-नेशनल कान्फ्रेंस ने आतंकवाद का बीज बोया : राम माधव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और नेशनल कान्फ्रेंस ने कश्मीर में आतंकवाद का बीज बोया और पाकिस्तान ने उस हालात का फायदा उठाया। उन्होंने कश्मीर में समस्याओं के लिए नेहरू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को संसद में जो कहा, वह ऐतिहासिक सत्य है। जम्मू -कश्मीर की समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए राम माधव ने कहा कि हमारा गठबंधन तो केवल ढाई साल सत्ता में था, लेकिन कांग्रेस दशकों तक गठबंधन में रही। ऐसे में जो भी समस्या आज आप देखते हैं उसके लिए जिम्मेदार वही दोनों दल हैं।

- भाजपा का कांग्रेस और नेशनल कान्फ्रेंस पर हमला, कश्मीर समस्या के लिए बताया जिम्मेदार

राम माधव फाइल फोटो

सुषमा स्वराज ने खाली किया सरकारी बंगला

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। यह जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट के जरिये साझा की। सुषमा ने ट्वीट किया, 'मैंने अपना सरकारी आवास 8, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली खाली कर दिया है। कृपया ध्यान रखें कि पहले के पते और फोन नंबर पर अब मुझसे संपर्क नहीं हो सकेगा।'

लंबे समय तक भाजपा की सबसे प्रमुख महिला चेहरा रहीं स्वराज हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी थीं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती हैं। 16वीं लोकसभा में वह मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से चुनाव जीती थीं। बता दें कि पिछले साल नवंबर में उन्होंने घोषणा की थी कि वह 2019 का आम चुनाव नहीं लड़ेंगी। नियमानुसार पूर्व सांसदों को पिछली लोकसभा भंग होने के एक महीने के भीतर अपने सरकारी आवास खाली करने होते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर 25 मई को 16वीं लोकसभा भंग कर दी थी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में समाचार पत्रों में ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित हुई थीं जिनमें कहा गया था कि विभिन्न राजनीति दलों के तमाम पूर्व संसद सदस्य नियमों की अनदेखी कर सरकारी आवासों में डटे हुए हैं। कुछ नेता तो वर्षों से बिना कोई भुगतान किए इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं।

रहेगी नजर

छह सप्ताह के अवकाश के बाद मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट 31 न्यायाधीशों के साथ एक जुलाई से शुरू करेगा अपना काम

अयोध्या और राफेल जैसे मामलों की होगी सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : छह सप्ताह के अवकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट एक जुलाई से खुल रहा है और अब उसे अयोध्या और राफेल जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुकदमों से निपटना होगा। राहुल गांधी ने राफेल मामले में 'चौकीदार चोर है' टिप्पणी को लेकर अपने खिलाफ चल रही अवमानना की कार्रवाई के लिए शीर्ष कोर्ट से माफी मांग ली थी, लेकिन मामले में सुनवाई अभी होनी है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व में कोर्ट 31 न्यायाधीशों के साथ एक जुलाई से अपना काम शुरू करेगा। संभावना है कि वह राफेल मामले से जुड़ी समीक्षा याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा। फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को शीर्ष कोर्ट ने 14 दिसंबर, 2018 को खारिज कर दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा व अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट के आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दायर की है।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 'चौकीदार चोर है' टिप्पणी में शीर्ष कोर्ट का गलत हवाला देने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर भी सुनवाई करेगी। गांधी इस मामले में माफी मांग चुके हैं और उन्हें अवमानना की कार्रवाई बंद करने का आग्रह किया है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना हक विवाद मामले में भी सभी की नजरें बंद कमरे में हुई सुनवाई के परिणाम पर टिकी रहेंगी। शीर्ष कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एफएम कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पैनल ने मामले का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए सुनवाई की थी। इस पैनल में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पांचू भी शामिल हैं। इन्हें आशा है कि इस विवादित मुद्दे का कोई न कोई सौहार्दपूर्ण हल जरूर निकलेगा। जस्टिस गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने पैनल को 15 अगस्त तक का समय दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में 14 याचिकाएं दायर की गई हैं। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लल्ला में बराबर-बराबर बांट दिया था। इसके अलावा कोर्ट वकीलों इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर तथा उनके एनजीओ 'लॉयर्स कलेक्टिव' के खिलाफ जांच करने और प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर भी सुनवाई करेगा। उनपर विदेशों से चंदा लेने और उस धन का इस्तेमाल करने में नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। यह याचिका वकीलों के एक स्वयंसेवी संस्थान 'लॉयर्स वॉइस' ने दायर की है। शीर्ष कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर भी सुनवाई करेगी। साथ ही जम्मू एवं कश्मीर से ही जुड़े संविधान के अनुच्छेद 35ए पर भी सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठकों में मिलेगा खजूर और भुना चना

नई दिल्ली, एएनआइ : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभाग की बैठकों में जलपान के दौरान बिस्किट नहीं परोसने के निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने इसकी जगह बैठकों में स्वास्थ्यवर्धक जलपान जैसे खजूर या भुना चना देने की सलाह दी है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में 19 जून को एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें मंत्रालय ने अपने सभी विभागों को तत्काल प्रभाव से आधिकारिक बैठकों के दौरान कुकीज, बिस्किट और अन्य फास्ट फूड परोसने से मना किया था। मंत्रालय ने कहा था कि इनकी जगह विकल्प के तौर पर बादाम, अखरोट, खजूर और भुना चना, लइया चना देने की सलाह दी है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'हम इस कदम खुश हैं। हमारे मंत्री स्वयं एक डॉक्टर हैं और वह फास्ट फूड से होने वाले नुकसान को जानते हैं। हम इस कदम को सहर्ष स्वीकार करते हैं।' बता दें कि इससे पहले मंत्रालय अपनी बैठकों प्लास्टिक वाली पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगा चुका है।

कह के रहेंगे माधव जोशी